गेहूं के आयात का सहारा लिया जाता है। उत्पादन, स्टाक स्थिति, वसूली की प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता, खुले बाजार मूल्यों आदि को ध्यान में रखते हुए गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया जाता है। केन्द्रीय पूल में गेहूं की सुगम स्टाक स्थिति की दृष्टि में, इस समय गेहूं का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कुल आवश्यकता और सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता के बीच लगभग पांच से छः लाख मीटरी टन के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा खाद्य तेलों का आयात किया जाता है। इस संबंध, राज्य व्यापार निगम को 20% की रियायती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आर०बी०डी० पामोलिन का आयात करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 20 प्रतिशत की रियायती दर पर चयन किए गए खाद्य तेलों का आयात करने की भी अनुमति दी गई है। खाद्य वनस्पति पामोलीन तेल के आयात को 20-4-1995 से 65 प्रतिशत ड्यूटी पर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया था। तथापि, खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन खाद्य तेल का आयात अधिक आयात डियूटी के तत्व के कारण उस सीमा तक नहीं किया गया जितनी सरकार द्वारा प्रत्याशा की गई थी। खाद्य तेल के आयात को सुविधाजनक और मितव्ययी बनाने के लिए नारियल के तेल, पाम करनल तेल, आर.बी.डी. पाम तेल और आर.बी.डी. पाम स्टेयरिन को छोड़कर सभी खाद्य तेलों को 1-3-95 से 30 प्रतिशत की घटी हुई ड्यूटी पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया था। 1995-96 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पामोलीन की 1.5 लाख मीटरी टन मात्रा का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत किया गया है।

केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में उत्तर प्रदेश द्वारा खाद्यान्नों का योगदान

6794. **प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा:**

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहा; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उस राज्य को आबंटित किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह):

(क) पिछले तीन विपणन मौसमों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए उत्तर प्रदेश में वसूल की गई गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है:—

(लाख मीटरी टन में)

रबी विपणन मौसम (अप्रैल से मार्च)	गेहूं
1992-93	4.97
1993-94	21.28
1994-95	14.06
1995-96	5.39
	(17.5.1995 को स्थिति के अनुसार)

खरीफ विपणन मौसम (अक्तूबर से सितम्बर)	चावल
1992-93	11.86
1993-94	12.95
1994-95	6.53
	(15.5.1995 को स्थिति के अनुसार)
1995-96	अभी शुरू नहीं हुआ है

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल की निम्नलिखित मात्रा आबंटित की गई थी :—

वर्ष	गेहूं	चावल
1992	7.19	4.20
1993	8.50	5.12
1994	11.86	5.50

Save Foodgrains Campaign in the Country

6795. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the broad details of the work undertaken by the save foodgrains campaign during the last three years year-wise, state-wise particularly in the State on Gujarat;

(b) the number of store houses/godowns provided for preserving foodgrains and the amount of subsidy being provided for the purpose;

(c) whether any assessment of the success of the campaign has been made by some voluntary organisations; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) The details of the work undertaken by the 'Save Grain Campaign' during the last three years, year-wise and State-wise area covered by Save Grain Campaign teams are given in the Annexure. [*See Appendix* 173, *Annexure No.* 44].

(b) The total number of non-metallic store-houses which were constructed/improved upon for preserving foodgrains at farm level during the last three years are 64561. For making improvement in the traditional grain storage structures and for construction of Pacca Kothi, incentive of Rs. 300/- per structure in the form of inputs, such as, metallic outlets, inlets, polythene sheet etc. are provided to the farmers. However, no subsidy is provided for this purpose.

(c) and (d) The work of Save Grain Campaign programmes had been evaluated by EFC Mission. The useful work done by Save Grain Campaign was generally endorsed by evaluating organisation.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से खरीदे गए मोटे अनाज

6796. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या **खाद्य मंत्री:** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से मोटे अनाज की खरीद का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा मोटे अनाजों की क्रय क्षमता में कमी के कारण, किसानों को अपना अनाज कम मूल्य पर बेचना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की क्रय क्षमता व इसके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किसी कार्य दल का गठन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) पिछले तीन विपणन मौसमों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए मूल्य समर्थन योजना के अधीन मोटे अनाज की वसूली निम्नानुसार है :—

(लाख मीटरी टन में)

विपणन मौसम	मोटे अनाज
1992–93	3.98
1993–94	0.26
1994–95 (15.5.1995तक)	नगण्य